खंड: 7, अंक: 11 नवंबर 2024 RNI- DELHIN/2021/84711
ISSN- 2584-2803 (Print)

# संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

## चुनावी प्राक्कलन: परिकल्पना बनाम संकल्पना

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस
वैश्विक अध्ययन केंद्र
(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)
दिल्ली विश्वविद्यालय

## संपादक

**प्रोफेसर सुनील कुमार**

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** director@cgs.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

## संपादक मंडल

**डॉ रमेश कुमार भारद्वाज**

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://www.mphighereducation.nic.in

**डॉ महेश कौशिक**

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** mkaushik@cgs.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://www.aurobindo.du.ac.in

**डॉ संध्या वर्मा**

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

**ई-मेल आई डी:** sverma@shyamlale.du.ac.in

**प्रोफाइल लिंक:** https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

**डॉ अभिषेक नाथ**

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

**ई-मेल आई डी:** tuesdaytrack@gmail.com

**प्रोफाइल लिंक:** https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

**© सीजीएस2024**

# संश्लेषण

## चुनावी प्राक्कलनः परिकल्पना बनाम संकल्पना

अनुक्रमिका

संपादकीय


1. महाराष्ट्र में महिला मतदान रुझानों एक विश्लेषण — दृष्टि साह 1–6
2. भारत में लोकतान्त्रिक संकल्पना और राजनीतिक दल – नरेंद्र 7–10
3. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024ः कोंकण क्षेत्र का अध्ययन
— अंकिता पांडे और नितिन 11–17
4. एक राष्ट्र, एक चुनावः भारत की आवश्यकता एवं महत्व
— शबनम और सविता कौशल 18–25
5. चुनावी प्राक्कलनः तथ्यपरक या कृत्रिम
— हितेन्द्र बारगल और प्रियंका बारगल 26–30
6. चुनावी प्राक्कलनः परिकल्पना बनाम संकल्पना — सजल जैन 31–38

## सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 76वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

जैसे–जैसे 2024 के महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी अनुमान राजनीतिक रणनीतियों और सार्वजनिक विचार–विमर्श दोनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तथापि, इन चुनावों का विश्लेषण करते समय, परिकल्पना व अवधारणा के मध्य अंतर करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक चुनावी व्यवहार की व्याख्या करने तथा परिणामों की भविष्यवाणी करने में एक अलग उद्देश्य पूरा करता है।

चुनावी अनुमान के संदर्भ में एक परिकल्पना सामान्य रूप से महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में परीक्षण योग्य मान्यताओं को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए, एक परिकल्पना यह हो सकती है कि राज्य स्तर के नेताओं को लोकप्रियता–जैसे कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन–मतदाता मतदान और पार्टी निष्ठा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विश्लेषक मतदान डेटा, पिछले मतदान पैटर्न व जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करके इस परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं, यह परीक्षण हुए कि क्या स्थानीय नेतृत्व इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय आख्यानों से अधिक प्रतिध्वनित होता है। इसके विपरीत, एक अवधारणा व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है जो इन चुनावों की व्याख्या को आकार देती है। क्षेत्रवाद जाति–आधारित राजनीति या सत्ता पक्ष का लाभ जैसी अवधारणाएँ चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले गहरे, दीर्घकालिक कारकों को समझने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, शिवसेना जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय गौरव का लाभ उठाया है।

जबकि झारखंड में, आदिवासी पहचान व कल्याण और विकास पर सरकार की नीतियाँ राजनीतिक वार्तालाप को आकार देंगी। ये अवधारणाएँ, तथापि सीधे परीक्षण योग्य नहीं हैं, किंतु विश्लेषकों को मतदान व्यवहार, अभियान के वादों व राजनीतिक माहौल की व्याख्या करने के माध्यमों को निर्देशित करती हैं।

चुनाव परिणामों का अनुमान लगाने में चुनौती इन तत्वों को संतुलित करने में है। परिकल्पनाएँ विशिष्ट, डेटा–संचालित भविष्यवाणियाँ प्रदान करती हैं, जबकि अवधारणाएँ मतदाता प्रेरणाओं को समझने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करती हैं। महाराष्ट्र व झारखंड में, सफल चुनावी अनुमान में पार्टी गठबंधन जैसे तात्कालिक कारकों (परिकल्पनाओं) और क्षेत्रवाद तथा सामाजिक–आर्थिक असमानताओं जैसे दीर्घकालिक गतिशीलता (अवधारणाओं) दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।

विषय की महत्ता तथा विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'चुनावी प्राक्कलनः परिकल्पना बनाम संकल्पना' विषय पर लेख आमंत्रित किये। उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ विषय के परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल शनिवार, 14 दिसंबर 2024

1

# महाराष्ट्र में महिला मतदान रुझानों एक विश्लेषण

दृष्टि साह

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

2019 के आम चुनाव में, महिला मतदाताओं ने 67.18% मतदान के साथ इतिहास रच दिया, आजादी के बाद पहली बार पुरुष मतदान को पीछे छोड़ते हुए और अपने बढ़ते चुनावी प्रभाव को रेखांकित किया। इस बदलाव ने भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मतदाता ब्लॉक के रूप में महिलाओं के बढ़ते महत्व को स्थापित किया। इस साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, 9.7 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 5 करोड़ से अधिक पुरुष थे, जबकि 4.6 करोड़ महिलाएं थीं। इन चुनावों को सही मायने में महिला–केंद्रित कहा जा सकता है, क्योंकि सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधनों ने सक्रिय रूप से महिला–समर्थक नीतियों और वादों के माध्यम से महिलाओं से अपील करने की कोशिश की, परिणामों को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना।

दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में से पांच में उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखी गई जब मतदाता पंजीकरण में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी। 30 अक्टूबर, 2024 को रिपोर्ट किए गए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, पंजीकरण में अंतर मामूली लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। विविध चुनावी गतिशीलता वाले राज्य में, ये पांच महिला–वर्चस्व वाले जिले सबसे अलग हैं, जिससे पार्टी की वफादारी, मुद्दा–आधारित चिंताओं और व्यक्तिगत उम्मीदवारों में उनकी मतदान प्राथमिकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यह प्रवृत्ति न केवल महिला मतदाताओं के महत्व को उजागर करती है, बल्कि राज्य के चुनावी परिदृश्य को आकार देने वाले व्यापक सामाजिक–राजनीतिक बदलावों को भी दर्शाती है।

## पंजीकृत मतदाता और प्राथमिकताएं

जैसा कि आंकड़ों में महाराष्ट्र के पांच जिलों पर प्रकाश डाला गया है, जहां महिला मतदाता पंजीकरण पुरुष पंजीकरण से अधिक है, रत्नागिरी कुल 13.3 लाख मतदाताओं में से 51.8%

महिलाओं के साथ आगे है, जो मतदाताओं में एक मजबूत महिला प्रतिनिधित्व का संकेत देता है। इसी तरह, नंदुरबार और सिंधुदुर्ग में, महिलाओं की पंजीकृत मतदाताओं में 50.7% हिस्सेदारी है, जो पुरुष मतदाताओं से थोड़ा पीछे है। गोंदिया कुल 11.2 लाख मतदाताओं में से 50.8ः महिलाओं के साथ निकटता के साथ है, जबकि भंडारा अपेक्षाकृत संतुलित लिंग अनुपात दिखाता है, जिसमें महिलाओं की संख्या 50.4% है। ये आंकड़े मतदाता पंजीकरण में लिंग अंतर को कम करने पर जोर देते हैं, इन जिलों के चुनावी परिदृश्य में महिलाएं एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रही हैं (तालिका 1)

तालिका 1रू 5 जिलों के कुल मतदाताओं में से पुरुष और महिला मतदाता

| जिला | कुल मतदाता | पुरुष | मादा |
|---|---|---|---|
| रत्नागिरी | 13.3 लाख | 6.4 लाख (48.1%) | 6.9 लाख (51.8%) |
| नंदुरबार | 13.2 लाख | 6.5 लाख (49.2%) | 6.7 लाख (50.7%) |
| गोंदिया | 11.2 लाख | 5.5 लाख (49.1%) | 5.7 लाख (50.8ः) |
| भंडारा | 10.1 लाख | 5.0 लाख (49.5%) | 5.1 लाख (50.4%) |
| सिंधुदुर्ग | 6.7 लाख | 3.3 लाख (49.2%) | 3.4 लाख (50.7%) |

नोटः सभी आंकड़े पूर्णांक दिए गए हैं।

महाराष्ट्र में सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि जिलों में चुनावी प्राथमिकताओं में आकर्षक विविधता है, जो महिला मतदाताओं की विभिन्न प्राथमिकताओं को दर्शाती है. रत्नागिरी और गोंदिया दृढ़ता से मुद्दा–केंद्रित के रूप में उभरे हैं, क्रमशः 75% और 70% महिला मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों या पार्टी की वफादारी पर मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि वे तय करते हैं कि किसे वोट देना है। दिलचस्प बात यह है कि रत्नागिरी में, महिला मतदाताओं ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दिखाई, जिससे जिले के मुद्दा–केंद्रित अभिविन्यास को और बल मिला। यह भंडारा के साथ तेजी से विरोधाभास है, जहां 65ः मतदाताओं ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर अपना भरोसा रखा है, जो उम्मीदवार–केंद्रित विकल्प का प्रदर्शन करते हैं। सिंधुदुर्ग एक अद्वितीय संतुलन प्रदान करता है,

जिसमें मतदाताओं के समान अनुपात (44%) दोनों मुद्दों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर जोर देते हैं, जो व्यापक चिंताओं और व्यक्तिगत गुणों पर दोहरे ध्यान का संकेत देते हैं। इस बीच, नंदुरबार अपने विविध वितरण के लिए खड़ा है, जहां प्राथमिकताएं मुद्दों (41%), व्यक्तियों (36%), और पार्टियों (23%) के बीच समान रूप से विभाजित हैं, जो अधिक सूक्ष्म मतदाता गतिशील का सुझाव देती हैं। पार्टी की वफादारी सभी जिलों में उल्लेखनीय रूप से कम है, लेकिन गोंदिया (10 फीसदी) और सिंधुदुर्ग (12 फीसदी) में सबसे कम है, जबकि रत्नागिरी और नंदुरबार पार्टियों के साथ मध्यम संरेखण प्रदर्शित करते हैं। ये विरोधाभास महिला मतदाताओं के व्यवहार में क्षेत्रीय बारीकियों को रेखांकित करते हैं, जो स्थानीय संदर्भों और अलग–अलग प्राथमिकताओं (तालिका 2) द्वारा आकार लेते हैं।

तालिका 2: महिला मतदाताओं की जिलेवार चुनावी प्राथमिकताएं

| जिला | चुनावी प्राथमिकताः | |
|---|---|---|
| रत्नागिरी | मुद्दे | 75 |
| | दावत | 25 |
| नंदुरबार | मुद्दे | 41 |
| | व्यक्ति | 36 |
| | दावत | 23 |
| गोंदिया | मुद्दे | 70 |
| | व्यक्ति | 20 |
| | दावत | 10 |
| भंडारा | व्यक्ति | 65 |
| | दावत | 19 |
| | मुद्दे | 16 |
| सिंधुदुर्ग | मुद्दे | 44 |

| | |
|---|---|
| व्यक्ति | 44 |
| दावत | 12 |

नोटः सभी आंकड़े पूर्णांक दिए गए हैं।

मुद्दे जो मायने रखते हैं

महिला मतदाताओं को प्रभावित करने वाले श्मुद्दोंश के संदर्भ में, कई प्रमुख चिंताएं उभरकर सामने आई, जिसमें विकास और शासन लोकप्रिय और कल्याणकारी उपायों को समाहित करने वाली एक व्यापक श्रेणी के रूप में सामने आए। शासन और लोक कल्याण नीतियों की प्रभावशोलता को दर्शाने वाला यह मुद्दा लगातार जिलों में प्रमुखता से सामने आया। इसके साथ ही, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, कानून और व्यवस्था, और भ्रष्टाचार जैसी विशिष्ट चिंताओं का क्षेत्र के आधार पर महत्व अलग–अलग था।

जिला स्तरीय विश्लेषण से हड़ताली रुझानों का पता चलता है। रत्नागिरी और गोंदिया में, जहां मुद्दा–आधारित मतदान (क्रमशः 75 फीसदी और 70 फीसदी) प्रभावी था, महिला मतदाताओं ने विकास और शासन (33 फीसदी और 93 फीसदी) पर जोर दिया। हालांकि, रत्नागिरी में, बेरोजगारी (50 फीसदी) अधिक महत्वपूर्ण थी, जो सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है। शासन पर गोंदिया का अत्यधिक ध्यान बेरोजगारी जैसी तात्कालिक चिंताओं पर कल्याणकारी उपायों के साथ एक संरेखण की ओर इशारा करता है। नंदुरबार में, जहां चुनावी प्राथमिकताओं को मुद्दों, व्यक्तियों और पार्टियों के बीच विभाजित किया गया था, महिलाओं ने बेरोजगारी (56 फीसदी) को प्राथमिकता दी, विकास और शासन (22 फीसदी) और महिला सशक्तिकरण (22 फीसदी) के साथ, विविध और स्थानीय चिंताओं को दर्शाते हुए।

भंडारा ने अपने उम्मीदवार–केंद्रित मतदान पैटर्न के बावजूद, विकास और शासन (50 फीसदी) को महिलाओं के लिए एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा, इसके बाद बेरोजगारी (33 फीसदी) और भेदभाव (17 फीसदी) का स्थान रहा। यह इंगित करता है कि व्यक्तिगत–केंद्रित जिलों में भी, शासन एक केंद्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। सिंधुदुर्ग में, जो मुद्दों और व्यक्तिगत–आधारित मतदान को संतुलित करता है, विकास और शासन (72 फीसदी) महिलाओं की चिंताओं पर हावी है, कानून और व्यवस्था (14 फीसदी) और बेरोजगारी (14 फीसदी) माध्यमिक मुद्दों के रूप में उभर रहे हैं, जो स्थिरता और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कुल मिलाकर, डेटा इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे विकास और शासन जिलों में एक एकीकृत मुद्दा बना हुआ है, जबकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसी स्थानीय चुनौतियां महिला मतदाताओं के बीच चुनावी प्राथमिकताओं को आकार देती हैं। व्यापक और स्थानीय चिंताओं के बीच यह गतिशील परस्पर क्रिया महिलाओं के मतदान व्यवहार को चलाने वाली जटिल प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालती है (तालिका 3)।

तालिका 3रू जिलेवार मुद्दे जिनके आधार पर महिला मतदाता मतदान करती हैं

| जिला | मुद्दे | : |
|---|---|---|
| रत्नागिरी | बेरोजगार | 50 |
| | विकास और शासन | 33 |
| | भ्रष्टाचार | 17 |
| नंदुरबार | बेरोजगार | 56 |
| | विकास और शासन | 22 |
| | महिला सशक्तिकरण | 22 |
| गोंदिया | विकास और शासन | 93 |
| | बेरोजगार | 7 |
| भंडारा | विकास और शासन | 50 |
| | बेरोजगार | 33 |
| | विभेदन | 17 |
| सिंधुदुर्ग | विकास और शासन | 72 |
| | बेरोजगार | 14 |
| | कानून और व्यवस्था | 14 |

नोटः सभी आंकड़े पूर्णांक दिए गए हैं।

2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारत के चुनावी परिदृश्य में महिला मतदाताओं की परिवर्तनकारी भूमिका की पुष्टि करता है। 2019 के आम चुनाव में पुरुष मतदाता मतदान को पार करने से लेकर उच्च महिला मतदाता पंजीकरण वाले जिलों में प्रमुख चुनावी गतिशीलता को आकार देने तक, महिला मतदाता अब एक निष्क्रिय जनसांख्यिकीय नहीं बल्कि एक निर्णायक चुनावी ताकत हैं। इन 5 जिलों के अध्ययन से पता चलता है कि महिला मतदाता पारंपरिक वफादारी पर ठोस मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक दलों के प्रचार और रणनीति को नया आकार दे रही हैं। यह बढ़ती व्यस्तता न केवल एक लिंग बदलाव का संकेत देती है, बल्कि नीतियों और शासन संरचनाओं की व्यापक मांग है जो उनकी आकांक्षाओं को संबोधित करती हैं। जैसा कि महिला मतदाता अपनी एजेंसी पर जोर देना जारी रखती हैं, महाराष्ट्र और पूरे भारत में लोकतंत्र पर उनका प्रभाव गहरा होने की ओर अग्रसर है, राजनीतिक खिलाड़ियों को सार्थक, समावेशी नीतियों के साथ जवाब देने के लिए चुनौती दी जाती है जो उनकी आवाज के साथ गूंजती हैं।

♦♦♦♦♦

2

# भारत में लोकतान्त्रिक संकल्पना और राजनीतिक दल

नरेंद्र

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में लोकतंत्र नागरिकों के जीवन का मुख्य विचार बन चुका है। लोकतांत्रिक संकल्पना को संजोय रखने में राजनीतिक दलों का मुख्य योगदान है। चुनावी प्रतिस्पर्धा, संस्थागत बदलाव, मध्यम वर्ग की सकारात्मक भागेदारी, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव आदि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा प्रदान कर रहें हैं। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद और इसके सामाजिक और भौगोलिक विस्तार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदला है इसका परिणाम यह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति झुकाव की ओर जा रही है और वामपंथी मोर्चा लगभग अपने पतन की ओर है। राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। राजनीतिक दल कई अहम क्षेत्रों में जनता और सरकार के बीच मुख्य कड़ी का काम करते हैं। वह मतदाताओं को जागरूक करते है, अपने विरोधी दल की खामियों को जनता के सामने लाते हैं। दूसरी और व्यक्ति अपनी इच्छाएं मतदान के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार दल राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ाने का माध्यम है और राजनीतिक समाधान के लिए तमाम वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। यह लेख दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले इसमें भारतीय दलीय व्यवस्था के मुख्य पहलूओं को समझा गया हैं। इसके बाद राजनीतिक दल और लोकतंत्र के सम्बन्धों को संक्षेप में बताया गया है।

## भारत में दलीय व्यवस्था और इसके मुख्य पहलू

राजनीतिक दल किसी खास परिवेश में कार्य करते है जिसके अपने संगठनात्मक उदेश्य होते हैं। जब इस परिवेश में बदलाव आता है तो उसका असर दलों पर भी पड़ता है और इसके अनुसार स्वंय को इसमें ढालने की कोशिश करते है। यह विचार कई रूपों में भारत की दलीय व्यवस्था में देखा जा सकता है। पहला, दलीय व्यवस्था (1952–1967) में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के साथ–साथ अधिकतर राज्यों  अपनी पकड़ बनाए हुए थी, इस मजबूत जन आधार की वजह से उस दौर को 'कांग्रेस व्यवस्था' के नाम से जाना जाता है (Kothari:

1964; 1173)। दूसरा, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विपक्ष का उदय हुआ, जिस कारण दलीय व्यवस्था (1967–1989) में ध्रुवीकरण देखा गया। इस दौर में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतती रही लेकिन कई राज्यों में गैर–कांग्रेसी विपक्षी दल अपना प्रभाव बढ़ा रहें थे। तीसरा, वर्ष 1990 के बाद भारत में बहुदलीय व्यवस्था देखी जा सकती है। कई गठबंधन की सरकारों की सरकारों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु परिवेश इस में बदलाव वर्ष 2014 में देखा जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी लोक सभा के चुनाव में भारत के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जन आधार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहीं हैं।

हर दलीय व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषता होती है, परंतु जब भारतीय संदर्भ मे इसे देखा जाता है तो इसके कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आते है। एक, राजनीतिक दलों के वैचारिक आंदोलन ने कांग्रेस के प्रभुत्व वाले दौर को बहुदलीय व्यवस्था में बदला और बाद में उसी से वजह से वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और अपना प्रभाव कायम करने में सफल रहीं। बिजेपी ने अपनी जीत को समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बताया और सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास का नारा दिया। अर्थात यह पहली बार था कि भारत में किसी गैर–कांग्रेसी दल को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। दूसरा, बीजेपी उन नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रही है जो देश में बड़ा बदलाव चाहते थे। चाहे यह बदलाव सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ा हो या अल्पसंख्यकों समेत सभी सामाजिक समूहों को खास पहचान देने का हो। परंतु अधिकतर राजनीतिक दल संगठनीय ढांचे, काम करने के तरीकों, लोगों को एकजुट करने वाले प्रयासों को लेकर एक दूसरे से मिलते–जूलते प्रतीत होते हैं और दलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती जा रहीं हैं। अपने बल–बूते पर निर्दलीय चुनाव जीत पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम बनी रहती है। परंतु भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बुनियादी पहलू बहुत मजबूत है जैसे समय पर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव आयोग आदि के कारण लोकतंत्र सही से कार्य कर पा रहा हैं। तीसरा, विपक्षी खेमे में गतिरोध का लाभ भारतीय जनता पार्टी को अधिक मिल रहा है। इसलिए वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय दलों के साथ अपाना समन्वय बढ़ाने का प्रयास कर कर रहीं।

राजनीतिक दल और लोकतंत्र

लोकतंत्र को चलाने और इसकी नींव मजबूत करने में राजनीतिक दलों की स्पष्ट भूमिका देखी जा सकती है। लोकतंत्र में सार्वजनिक समस्याओं को राजनीतिक दल जनता के सामने प्रस्तुत करते

हैं ताकि समान्य जनता उन्हें समझ सके। जब विभिन्न राजनीतिक दल समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार रखते है तो जनता इन समस्याओं पर अपना निर्णय करती है। इसके अलावा उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें विजयी बनाना प्रत्येक राजनीतिक दल का उदेश्य होता है । सत्ता प्राप्ति के बाद सभी दल अपना जन आधार बढ़ाने के साथ–साथ जनता से किए वादों को पूरा करने का प्रयास करते है ताकि वह फिर से चुनाव जीत सके। कोई भी सरकार उस समय सही प्रकार से कार्य कर सकती है जब शासन की विभिन्न संस्थाएं एक–दूसरे से सहयोग करें और इस सहयोग में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका निभाता है। चाहे संसदीय शासन हो या अध्यक्षात्मक शासन, राजनीतिक दल ही इस कार्य को सम्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण अमेरिका में देखा जा सकता है जहां दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया। इसी प्रकार यदि भारत में लोकतांत्रिक संकल्पना को सही प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक दल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है।

## संदर्भ सूची


- Kothari. Rajni (1964) ‘The Congress 'System' in India’ Vol. 4, No. 12, December pp. 1161-1173, Asian Survey.(https://www.jstor.org/stable/pdf/2642550. pdf?refreqid = fastlydefault%3A8886598ead8f8c1767f031802d59e326&ab_segments=&initiator=&acceptTC=1)
- Chakraborty. Ritabrata (2021) ‘An enduring system: The relevance of the Congress System as a unique mode of socio-political structural set-up endures, offering lessons for all parties competing in the electoral fray’ the telegraph.


♦♦♦♦♦

3

# महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: कोंकण क्षेत्र का अध्ययन

अंकिता पांडे

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नितिन

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

महाराष्ट्र, परंपराओं और प्रगतिशील आदर्शों की भूमि, भारत की विविधता का एक सूक्ष्म जगत है। अपनी जीवंत संस्कृति और विरासत के साथ, यह भारत के सबसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से विविध राज्यों में से एक है। मुंबई के हलचल भरे महानगर से, जो भारत की वित्त राजधानी है, कोंकण परिदृश्य के चमत्कारों तक, महाराष्ट्र विशिष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य फिर से तस्वीर में आता है क्योंकि इसने 2024 में एक और महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव देखा। राज्य को 6 क्षेत्रों और 36 जिलों के तहत विभाजित 288 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक शहरी, ग्रामीण और अर्ध–शहरी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अपने राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाताओं के लिए जाना जाता है, राज्य में कई दबाव वाले मुद्दों या चुनौतियों के आधार पर एक अलग मतदान पैटर्न है, और कोंकण क्षेत्र इस तरह की गतिशीलता का अपवाद नहीं है। इस लेख में, हम महाराष्ट्र के प्रमुख क्षेत्रों में से एक की विशिष्टताओं से निपटेंगे, जो कोंकण है।

## कोंकण क्षेत्र का अवलोकन

महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता की एक विशाल भूमि है, जिसमें सह्याद्री पहाड़ियों से अरब सागर तक फैली 720 किलोमीटर की तटरेखा है। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली भौगोलिक स्थलाकृति होने के अलावा, इसका राजनीतिक परिदृश्य भी उतना ही अनूठा है। 7 जिलों– मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के तहत कुल 75 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करते हुए कोंकण राज्य के राजनीतिक आख्यान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह क्षेत्र भी है जहां से कुछ लोकप्रिय उम्मीदवारों ने

चुनाव लड़ा, जैसे कि आदित्य ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, नारायण टाटू राणे (भाजपा) रत्नागिरी–सिंधुदुर्ग क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे (शिवसेना शिंदे गुट) ठाणे में कोपरी–पचपाखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और मिलिंद देवड़ा (शिवसेना शिंदे गुट) वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।

कोंकण क्षेत्र से उभरने वाले प्रमुख मुद्दे

सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समीक्षा श्रृंखला के तहत आयोजित एक ऑफलाइन क्षेत्र चुनाव सर्वेक्षण के तहत, सभी लिंगों और आयु रचनाओं को शामिल करते हुए स्थानीय आबादी के साथ बातचीत करने के बाद, इस विशेष मुद्दे के मतदाताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभरे, और वे इस प्रकार हैं।

- मराठा आरक्षणः बेहतर जीवन स्तर, आर्थिक अवसरों और आजीविका के साधनों की तलाश में भारत के अन्य हिस्सों से प्रवासियों की एक बड़ी आमद के कारण, महाराष्ट की जनसांख्यिकी बदल रही है। जब मूल लोगों से पूछा गया, तो यह कहा गया कि स्थानीय लोग अपनी नौकरी के अवसर खो रहे हैं, और इस प्रकार मराठा समुदाय से मराठा आरक्षण को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की अधिक मांग है ताकि शैक्षिक और नौकरी के लाभ सुरक्षित हो सकें।

- भाषा अवरोधः कोंकण क्षेत्र मराठी संस्कृति का आधार है। हालांकि, महानगरीय संस्कृति और वैश्वीकरण के कारण, मूल निवासी अंग्रेजी और हिंदी के साथ मराठी भाषा को दरकिनार महसूस कर रहे हैं, और इस प्रकार नाराजगी उभरी है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी भाषाई पहचान खतरे में है, और सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर मराठी को प्राथमिकता देने की मांग है। इसलिए, भाषा की बाधा निस्संदेह क्षेत्रीय और राष्टोय राजनीतिक दलों के लिए एक नारा बन गई है।

- विकासात्मक परियोजनाओं का हस्तांतरणः एक प्रमुख मुद्दा जिसके कारण कोंकण क्षेत्र में भी असंतोष पैदा हुआ है, वह है महाराष्ट से गुजरात जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों में विकासात्मक या बुनियादी ढाचा परियोजनाओं का हस्तांतरण। चाहे वेदांता–फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना हो या मुंबई के लिए मूल रूप से नियोजित अंतर्राष्टोय वित्तीय केंद्र, स्थानीय लोग इन बदलावों को राजनीतिक पैंतरेबाजी के परिणामस्वरूप देखते हैं जो राज्य की आर्थिक संभावनाओं को प्रतिबंधित करता है।

• राजनीतिक नेतृत्व पर प्रतियोगिताय शिवसेना और एनसीपी (राष्टोय कांग्रेस पार्टी) में विभाजनः शिवसेना (उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (भाजपा के साथ अजीत पवार का गठबंधन और कांग्रेस के साथ शरद पवार का गठबंधन) के भीतर विभाजन ने पारंपरिक वोट बैंकों को और खंडित कर दिया है। मतदाता अब विभाजित हैं, एक अप्रत्याशित राजनीतिक परिदृ श्य बना रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उद्धव ठाकरे को एक और मौका मिलना चाहिए क्योंकि महामारी के कारण उनकी क्षमता बाधित हुई थी, लेकिन अन्य लोगों की राय है कि एकनाथ शिंदे सीएम उम्मीदवार के लिए अंतिम चेहरा हैं. यह भी देखा गया कि उद्धव ठाकरे के पिता के बाला साहेब ठाकरे की आधिकारिक शिवसेना के विभाजन के बाद उनके लिए बनाई गई सहानुभूति की लहरें अधिकांश मतदाताओं से मेल नहीं खाती थीं। कई निर्वाचन क्षेत्रों में, उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे लोगों की पसंद थे।

मतदान के पैटर्न

वोटिंग पैटर्न एक मतदाता के मानस को दर्शाता है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के आकार का होता है। वे बताते हैं कि मतदाता किस आधार पर और किस आधार पर किसी पार्टी को वोट देते हैं। क्या यह किसी व्यक्ति, विचारधारा या स्वयं राजनीतिक दल पर आधारित है? कई कारक मतदाताओं के मतदान निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जैसे धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक वर्ग, क्षेत्रीय गौरव और कुछ आकांक्षाएं। कोंकण क्षेत्र में, मतदान पैटर्न हमेशा क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के प्रति वफादारी से प्रभावित रहा है। हालांकि, इस बार कुछ नए और अधिक पैटर्न सामने आए हैं।

• जाति और समुदायः इस क्षेत्र के मतदान पैटर्न में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। संख्या में प्रभावशाली मराठा समुदाय अक्सर चुनावी नतीजों को प्रभावित और निर्धारित करता है. हालांकि, सामान्य श्रेणी के लोग, दलित और बड़े पैमाने पर ओबीसी, तेजी से अपनी राजनीतिक आवाज पर जोर दे रहे हैं।

• युवा फैक्टररू युवा मतदाताओं की बढ़ती जनसांख्यिकी ने चुनावों में एक नया आयाम जोड़ा है। जाति, वर्ग और लिंग की गतिशीलता के बावजूद, पहली बार मतदान करने वाले मतदाता अब भाजपा द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे युवा–केंद्रित नीतियों और डिजिटल अभियानों की ओर अधिक झुकाव महसूस कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, युवाओं के तहत, यदि हम पुरुषों का उदाहरण लेते हैं, तो श्लाडला भाई योजना श राज्य सरकार द्वारा पुरुष युवाओं को वित्तीय सहायता और

कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।

• महिला मतदाताः महिला मतदाता, जो आबादी का आधा हिस्सा हैं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा मतदाता आधार हैं। और उन्हें सशक्त बनाने के लिए और उनके संभावित वोटों को बरकरार रखने के लिए, योजनाएं और नीतियां एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय योजना थी श्मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजनाश। जिसका उद्दश्य राज्य में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना है, जो डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत कर सकती है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि योजनाओं और नीतियों की मतदाताओं के मतदान पैटर्न को बदलने और बदलने की अधिक भूमिका है।

• धार्मिक राजनीतिः यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से शिवसेना के गढ़ के तहत रहा है, जिसमें एक मजबूत हिंदुत्व आधार है। इसलिए मराठा पहचान से जुड़ी धार्मिक पहचान मतदान पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. हालांकि, ठाकरे गुट के धर्मनिरपेक्ष राजनीति की ओर बढ़ने से विभाजन पैदा हो गया है।

• शहरी बनाम ग्रामीण विभाजनः नवी मुंबई जैसे शहरी केंद्र विकास की कहानी के कारण भाजपा की ओर झुकते हैं, कोंकण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र अक्सर क्षेत्रीय दलों के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। यहां कृषि संकट, मछली पकड़ने के उद्योग की चिंताएं और बेरोजगारी जैसे मुद्द कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो ग्रामीण मतदान व्यवहार को आकार देती हैं।

कोंकण क्षेत्र में बदलती गतिशीलता

महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव देखा गया है, खासकर हाल के वर्षों में, जो बदलते गठबंधनों, नए शक्ति केंद्रों और उभरती राजनीतिक रणनीतियों से प्रेरित है। कई प्रमुख कारक इन गतिशीलता को प्रभावित कर रहे हैं–

• कांग्रेस से शिवसेना में स्थानांतरणः महाराष्ट के कोंकण क्षेत्र का अपना विशेष राजनीतिक क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से, यह कांग्रेस पार्टी का आधार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। जो इलाका पहले कांग्रेस का क्षेत्र था, वह अब शिवसेना का अधिकार क्षेत्र बन गया है। शिवसेना, जो अब क्रमशः एकनाथ शिंदे और अंत में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुटों में विभाजित है, क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समूह बन गई है। मुंबई महानगर

क्षेत्र सहित सबसे शहरीकृत और औद्योगिक क्षेत्र, 75 विधायकों को विधानसभा और 12 सदस्यों को लोकसभा में भेजता है। महाराष्ट्र में कोंकण तटीय डिवीजन, जिसमें सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले शामिल हैं, इस क्षेत्र का गठन करते हैं।

- आर्थिक परिवर्तनः कोंकण क्षेत्र ने बुनियादी ढाचे के विकास और आत्मनिर्भरता द्वारा चिह्नित तेजी से आर्थिक परिवर्तन का अनुभव किया है। इस आर्थिक विकास ने राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया है, जिसमें स्थानीय नेताओं ने विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया है। इस क्षेत्र ने बेहतर सड़कों, बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर उपयोगिताओं के साथ बुनियादी ढांचे में काफी विकास का अनुभव किया है। इसका परिणाम माल और लोगों की अधिक प्रभावी आवाजाही के रूप में सामने आया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में मदद मिली है। सहकारी पारिस्थितिक तंत्र का विकास उन पारिस्थितिक तंत्रों में स्थानीय आर्थिक गतिविधि को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण चालक है। उदाहरण के लिए, छत्रपति शाहू काजू सहकारी ने एक बहुआयामी बाजार लिंकेज दृष्टिकोण लागू किया है जिसमें बी 2 बी संबंध, पारंपरिक बाजारों के साथ जुड़ाव और उत्पाद की गुणवत्ता और ब्रांड विकास पर जोर दिया गया है। इन आर्थिक बदलावों के कारण, राजनीतिक स्थान भी प्रभावित हुआ है, जिससे स्थानीय अधिकारी आर्थिक विकास और उद्यमशीलता की दृष्टि की तलाश कर रहे हैं। क्षेत्र में आर्थिक विस्तार ने इसे राज्य चुनावों में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में बदल दिया है, जहां बड़े राजनीतिक दल राज्य नियंत्रण के लिए होड़ करते हैं।

- स्थानीय मुद्द और सक्रियताः इस क्षेत्र में स्थानीय कार्रवाई की परंपरा है, विशेष रूप से औद्योगिक परियोजनाओं पर। पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के आधार पर स्थानीय आबादी द्वारा कई औद्योगिक परियोजनाओं का विरोध किया गया है। इस सक्रियता ने क्षेत्र में नीतिगत बहस को प्रभावित किया है, लेकिन अब सक्रियता अधिक मजबूत हुई है। उदाहरण के लिए, कोंकण जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग में परियोजनाओं, उदाहरण के लिए, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नानर रिफाइनरी, को बार–बार स्थानीय आबादी द्वारा उठाए गए मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो पर्यावरणीय गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के डर से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, नानर रिफाइनरी सुविधा के खिलाफ विरोध ने अंततः पूरी परियोजना को स्थानांतरित करने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय में योगदान दिया। लेकिन लड़ाई जारी है क्योंकि नई परियोजनाएं और समस्याएं दिखाई देती हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वे क्षेत्र के पर्यावरण और कमाई की रक्षा के लिए हैं।

• बदलते पार्टी टंडः पिछले 34 सालों से महाराष्ट में कोई भी एक पार्टी स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बना पाई है। गठबंधन की राजनीति की यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है, महायुति (भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी) और महा विकास अघाड़ी (कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट, और शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट) जैसे गठबंधनों के प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। हालांकि, 2024 के विधानसभा चुनावों के हालिया परिणामों ने महाराष्ट राज्य में अन्य सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभारा। और इसके साथ, हम देख सकते है कि वंशवादी राजनीति धीरे–धीरे कैसे स्थानांतरित हो रही है या राज्य में स्थानांतरित हो रही है।

• राज्य की राजनीति में भूमिकाः महाराष्ट के 288 विधानसभा क्षेत्रों में से 75 के साथ, मुंबई में 36 निर्वाचन क्षेत्रों सहित, अध्ययन राज्य चुनावों में कोंकण क्षेत्र के महत्व पर केंद्रित है। जिस इलाके में अलग–अलग गुट सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक ताकत और उपस्थिति राजनीतिक दलों को इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार और रणनीति बनाने की इच्छा देती है। कोंकण क्षेत्र में, यह अधिक सीटें पाने के लिए सबसे अच्छा लाभ हासिल करने के लिए राजनीतिक गठबंधनों का खेल है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर प्रमुख खिलाड़ियों, महायुति सत्तारूढ़ गठबंधन और महा विकास अघाड़ी विपक्ष की नजर है।

इसलिए, पिछले वर्षों की तुलना में, कोंकण बेल्ट निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों के लिए एक अनुमानित जमीन से राष्ट्रीय दलों की शुरूआत के साथ प्रतिस्पर्धी मैदान बन गया है.

वर्तमान परिदृश्य

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, जिसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट कहा गया था, ने आखिरकार अपने परिणामों में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाए हैं। पारंपरिक शिवसेना गढ़ को एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना से हार का सामना करना पड़ा क्योंकि यूबीटी ने 2 सीटें हासिल कीं, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने 57 सीटें हासिल कीं। इसी तरह, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (जिसे 10 सीटें मिलीं) को अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से हार का सामना करना पड़ा। (41 सीटें हासिल कीं)। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी 288 में से 132 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

ने केवल 16 सीटें हासिल कीं। कोंकण क्षेत्र में भी, 75 निर्वाचन क्षेत्रों में से, महायुति गठबंधन ने लगभग 50 निर्वाचन क्षेत्रों को सुरक्षित किया, इस प्रकार एक बड़ी जीत का संकेत दिया और क्षेत्र में अपनी पकड़ और प्रभाव को और मजबूत किया। इस प्रकार बदली हुई और बदलती गतिशीलता बढ़ते ध्रुवीकरण और मतदाताओं की विकास—केंद्रित अपेक्षाओं का संकेत दे सकती है जो इस क्षेत्र के साथ—साथ राज्य के राजनीतिक भविष्य को बदल सकती है या फिर से आकार दे सकती है।

♦♦♦♦♦

4

# एक राष्ट्र, एक चुनावः भारत की आवश्यकता एवं महत्व

**शबनम**

शोधार्थी, शिक्षक प्रशिक्षण एवं गैर–औपचारिक शिक्षा विभाग (IASE), शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया

**सविता कौशल**

प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण एवं गैर–औपचारिक शिक्षा विभाग (IASE), शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया

## परिचय

भारत का लोकतंत्र अपनी चुनावी प्रक्रिया की सक्रियता और जीवंतता पर आधारित है, जो प्रत्येक नागरिक को शासन के निर्माण और विकास में सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 400 से अधिक चुनाव आयोजित किए जा चुक हैं, जो भारतीय निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि, बार–बार और असमान अंतराल पर होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक बोझ, आर्थिक संसाधनों पर दबाव, और विकासात्मक परियोजनाओं में व्यवधान जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को पुनः प्रासंगिक बना दिया है। एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा, जिसे समकालिक चुनाव भी कहा जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्रों को एकीकृत करने का सुझाव देती है। इस प्रणाली के तहत, मतदाता एक ही दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में दोनों स्तरों की सरकारों के लिए मतदान कर सकते हैं (विश्व बैंक, 2020)। हालांकि, यह प्रक्रिया देश भर में चरणबद्ध तरीके से आयोजित हो सकती है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाना, बार–बार चुनावों के कारण उत्पन्न होने वाली तार्किक और आर्थिक चुनौतियों को कम करना, और प्रशासनिक मशीनरी पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करना है (कपूर एवं मेहता)। 2024 में भारत में चुनावों पर एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें ष्एक राष्ट्र,

एक चुनाव प्रणाली" को लागू करने के लिए एक व्यवहारिक रोडमैप दिया गया। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को स्वीकार कर इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस प्रस्ताव के समर्थकों का मानना है कि यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर सकती है, चुनावी खर्चों को काफी हद तक कम कर सकती है, और नीतिगत निरंतरता को प्रोत्साहन दे सकती है समकालिक चुनाव प्रणाली के संभावित लाभ अनेक हैं। बार–बार चुनाव कराने की आवश्यकता समाप्त होने से प्रशासनिक संसाधन अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा सकेंगे। चुनाव संबंधी खर्चों में कटौती के अलावा, विकास परियोजनाओं की गति भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनावों के दौरान प्रायः विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली के तहत दीर्घकालिक नीतियों को लागू करने और शासन में स्थिरता लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

हालांकि, इस विचार के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सबसे पहले, इस प्रणाली को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल प्रक्रिया है और जिसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति और गहन विचार–विमर्श अनिवार्य है। इसके अलावा, आलोचक यह तर्क देते हैं कि यह प्रणाली क्षेत्रीय दलों की भूमिका को सीमित कर सकती है और भारत की विविधता पूर्ण लोकतांत्रिक संरचना को प्रभावित कर सकती है। अतः, एक राष्ट्र, एक चुनाव भारत के लोकतांत्रिक और प्रशासनिक तंत्र में सुधार लाने का एक अत्यंत प्रासंगिक और संभावित रूप से लाभकारी प्रस्ताव है। इसके कार्यान्वयन के लिए समग्र अध्ययन, हितधारकों के बीच व्यापक संवाद, और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह न केवल चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल और किफायती बनाएगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली

एक राष्ट्र, एक चुनाव का तात्पर्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने की प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य न केवल चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुगठित और कुशल बनाना है, बल्कि बार–बार चुनावों से जुड़े वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक प्रभावों को भी कम करना है। यह अवधारणा भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार लाने और शासन में स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली का भारत के संदर्भ में आवश्यकता और महत्व

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली विभिन्न चुनावों से जुड़े भारी वित्तीय खर्च को कम करने का एक प्रभावी समाधान है। प्रत्येक चुनाव के आयोजन में मानव संसाधन, उपकरण, सुरक्षा बलों की तैनाती, और अन्य प्रबंधों पर भारी व्यय होता है, जो देश की वित्तीय क्षमता पर दबाव डालता है। इस प्रणाली के माध्यम से इन खर्चों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। बचाए गए संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, और अन्य विकासात्मक योजनाओं में किया जा सकता है, जिससे न केवल वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी सीधा लाभ मिलेगा। यह प्रणाली राष्ट्र के समग्र विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसके अतिरिक्त, चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) प्रशासनिक कार्यों और विकास परियोजनाओं को प्रभावित करती है। इस आचार संहिता के लागू होने से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं ठप हो जाती हैं, जिससे नीतिगत अनिश्चितता उत्पन्न होती है। बार–बार चुनावों के कारण यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली से आदर्श आचार संहिता को बार–बार लागू करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी। इससे नीति–निर्माण और कार्यान्वयन में निरंतरता आएगी, जो जनता के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करेगा।

शासन में निरंतरता और स्थिरता लाने में भी यह प्रणाली सहायक सिद्ध हो सकती है। देश में लगातार होने वाले चुनावों के कारण राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावी तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, जिससे शासन और जनहितैषी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इससे विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की गति धीमी हो जाती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली अपनाने से चुनावी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सरकारें विकास और लोक कल्याणकारी नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। यह व्यवस्था शासन में स्थिरता लाने और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

यह धारणा कि समकालिक चुनाव क्षेत्रीय दलों को अप्रासंगिक बना देंगे, सही नहीं है। वास्तव में, यह प्रणाली क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय चुनाव अभियानों की छाया से बाहर लाने में मदद कर सकती है। इससे क्षेत्रीय दलों को अपनी नीतियों और जन आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय दलों की भूमिका मजबूत होगी और राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रभाव भी बढ़ेगा।

इसके साथ ही, एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली संसाधनों के कुशल प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। वर्तमान में अलग–अलग चुनावों के लिए बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों, और अन्य संसाधनों की तैनाती करनी पड़ती है। इससे उनके प्राथमिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और प्रशासनिक तंत्र पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। समकालिक चुनावों से बार–बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे संसाधनों का बेहतर और कुशल उपयोग संभव होगा। इससे सरकारी अधिकारी और संस्थान अपनी मूल जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

इसके अलावा, यह प्रणाली समावेशी राजनीतिक अवसर प्रदान करती है। अलग–अलग चुनावों में अक्सर कुछ नेता विभिन्न स्तरों पर एक साथ चुनाव लड़कर प्रमुख भूमिका में आ जाते हैं, जिससे अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। समकालिक चुनावों के माध्यम से राजनीतिक दलों के भीतर जिम्मेदारियों और अवसरों का संतुलन स्थापित होगा। यह व्यवस्था अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करेगी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी।

अंततः, एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली शासन और विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करती है। बार–बार चुनावी गतिविधियों के कारण राजनीतिक दलों और नेताओं का ध्यान शासन से भटक जाता है, जिससे विकास और प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। चुनावों को एक साथ आयोजित करने से सरकारें जनता की आवश्यकताओं और दीर्घकालिक विकास योजनाआं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। इस प्रणाली के माध्यम से देश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता आएगी, जो राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण के लिए अनिवार्य है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणालीः चुनौतियां

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक हैं, जिनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, और 174 जैसे प्रावधानों का संशोधन शामिल है। यह प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए संसद और राज्यों की व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी, जो विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके हितों को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों के बीच इस प्रणाली पर व्यापक सहमति बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय दल जहां इस प्रणाली का समर्थन कर सकते हैं, वहीं क्षेत्रीय दल इसे अपने राजनीतिक अस्तित्व और प्राथमिकताओं के लिए बाधा मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समकालिक चुनाव के कारण राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन पर असर पड़ने की

आशंका है। इसके अलावा, संवैधानिक संकट की संभावना भी बनी रहती है। यदि किसी राज्य या केंद्र की सरकार बहुमत खो देती है और समय से पहले चुनाव की आवश्यकता होती है, तो यह समकालिक चुनाव की अवधारणा को बाधित कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करना या चुनाव स्थगित करना संवैधानिक और प्रशासनिक संकट उत्पन्न कर सकता है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां भी एक बड़ी चुनौती हैं। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी की पर्याप्त उपलब्धता, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण और सुरक्षा बलों की तैनाती करना प्रशासनिक रूप से बेहद जटिल कार्य होगा। मतदाताओं के बीच जागरूकता की कमी और मतदान प्रक्रिया की सटीकता भी चिंता का विषय है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खासकर कम शिक्षित या पहली बार वोट डालने वालों के बीच। इससे मतदान प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली के लागू होने से क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और मुद्दों को राष्ट्रीय चुनावों की छाया में दबने का खतरा है, जिससे स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज किया जा सकता है।

हालांकि लंबे समय में इस प्रणाली से वित्तीय बचत हो सकती है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ईवीएम और वीवीपीएटी की खरीद, प्रशिक्षण, और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारी वित्तीय और प्रशासनिक निवेश की आवश्यकता होगी। इससे प्रशासनिक तंत्र पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। भारत के संघीय ढांचे पर इसका प्रभाव एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि यह राज्यों की स्वायत्तता और उनके शासन संबंधी प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। अंततः, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में इस प्रणाली को लागू करना कठिन हो सकता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं होती हैं, जिन्हें संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है( श्रिवास्तव, 2020)।

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली पर भारतीय के नागरिक दृष्टिकोणः उच्च स्तरीय समिति

भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करने की व्यवहार्यता का आकलन करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समिति ने जनता और राजनीतिक दलों से व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त की और विषय विशेषज्ञों से परामर्श किया। समिति ने इस महत्वपूर्ण चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों का मूल्यांकन किया। इसके निष्कर्षों में शासन, संसाधनों के प्रबंधन

और जन भावना पर प्रस्तावित सुधार के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, समिति ने प्रमुख संवैधानिक संशोधनों का सुझाव दिया है और समकालिक चुनावों के भारत की चुनावी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव चुनावों पर उच्च–स्तरीय समिति को देश भर से व्यापक जन प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों सहित कुल 21,500 से अधिक प्रस्तुतियां प्राप्त हुईं। इन प्रतिक्रियाओं में से 80% ने इस अवधारणा का समर्थन किया, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों से सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। राजनीतिक दलों ने भी इस परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें 47 दलों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने समकालिक चुनावों का समर्थन किया, इसे संसाधनों के अनुकूलन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला बताया, जबकि 15 दलों ने संभावित अलोकतांत्रिक प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने की चिंता व्यक्त की।

समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और कानूनी विशेषज्ञों सहित विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श किया। इनमें से अधिकांश विशेषज्ञों ने बार–बार चुनावों से होने वाले संसाधनों के अपव्यय और सामाजिक–आर्थिक व्यवधानों को रेखांकित करते हुए समकालिक चुनावों का समर्थन किया। आर्थिक हितधारकों, जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (FICCI), और एसोचौम (ASSOCHAM) ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने चुनावी व्यवधानों और लागत को कम करने के माध्यम से आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर जोर दिया।

एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली का कार्यान्वयनः उच्च स्तरीय समिति सिफारिश

इस पहल के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए समकालिक चुनाव संभव हो सके। समिति ने इसे लागू करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश कीरू पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का समकालिक किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को इन विधायी चुनावों के साथ 100 दिनों के भीतर समकालिक किया जाएगा।

समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा निर्वाचक सूची तैयार करने में पाई गई अक्षमताओं की पहचान की और एकल निर्वाचक सूची और एकल चुनाव फोटो पहचान पत्र (EPIC) अपनाने की सिफारिश की। इस एकीकरण का उद्देश्य त्रुटियों और पुनरावृत्तियों को कम करना और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं ने बार–बार होने वाले चुनावों के प्रतिकूल प्रभावों, जैसे मतदाता थकान और शासन में व्यवधान, पर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रस्तावित समकालिक चुनाव मॉडल से इन समस्याओं के समाधान की अपेक्षा की जाती है, जो एक अधिक स्थिर और कुशल चुनावी और शासन ढांचे को बढ़ावा देगा (विधि एवं न्याय मंत्रालय,2024)।

निष्कर्ष

राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली, केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं हैं, बल्कि वे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक समावेशी, स्थिर और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। हालांकि, इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे संविधान संशोधन की जटिलता, व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता, और क्षेत्रीय दलों की चिंताओं का समाधान। फिर भी, समकालिक चुनावों से शासन में दीर्घकालिक स्थिरता, वित्तीय कुशलता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने की संभावना है। यह दृष्टिकोण गहन विचार–विमर्श, व्यापक सहमति, और ठोस रणनीति के साथ लागू किया जाए तो यह भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक सुदृढ़ कर सकता है।

संदर्भ सूची


- कपूर, डी. एवं मेहता, पी. बी. (2017). भारत में निर्वाचन लोकतंत्र का भविष्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- विधि एवं न्याय मंत्रालय. (2024). एक राष्ट्र, एक चुनाव, भारत सरकार.
- विश्व बैंक. (2020). निर्वाचन प्रबंधन और लोकतांत्रिक शासन पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रभाव. https://www-worldbank-org/
- श्रिवास्तव, आर.(2020). भारत में चुनावी सुधारः चुनौतियां और संभावनाएं. नई दिल्लीः मनोहर पब्लिशर्स.
- https://onoe.gov.in/HLC-Report-en
- https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/simultaneous_elections/79th_Report.pdf
- https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/simultaneous_elections/NITI_AYOG_
- EPORT_2017.pdf One Nation, One Election
- http://www.india.gov.in/
- https://eci.gov.in/
- http://lawcommissionofindia.nic.in/
- http://parliamentofindia.nic.in/


♦♦♦♦♦

5

# चुनावी प्राक्कलनः तथ्यपरक या कृत्रिम

**हितेन्द्र बारगल**

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, (म.प्र.), भारत

**प्रियंका बारगल**

शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (म.प्र.), भारत

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को अंग्रेजो से तो आजादी प्राप्त हो गई पर कई समस्याओ जैसे विभाजन की त्रासदी, दंगे, आगजनी, भुखमरी, कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों द्वारा भी बंटवारे की मांग करना, देश को पड़ोसी देशो के आक्रमण से बचाने के साथ, देश का समुचित विकास करने हेतु तथा देश को सही तरीके से चलाने के लिए, भारतीय संविधान के निर्माताओ द्वारा देश को सशक्त बनाने और देश को सही नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई ,जिससे देश में चुनाव प्रकिया निर्बाध रूप से संचालित की जा सके।

78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू के शब्दों में "भारत में सफलतापूर्वक चुनाव संचालित करने से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को ताकत मिलती है।""

सर्वप्रथम वर्ष 1951– 52 में जब देश के पहले चुनाव संपन्न हुए, तो लोकसभा चुनाव के लिए ₹ 25000 खर्च तय किया गया था,जो 1971 में 35000, 1980 में 1 लाख से बढ़ते–बढ़ते 2014 में 70 लाख हो गया ,वही वर्ष 2024 हेतु यह खर्च लगभग 95 लाख हो गया है। चुनाव में एक दल द्वारा किए गए खर्च की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उम्मीदवार के लिए यह सीमा तय की गई है।

चुनावी खर्च की परिकल्पना की अगर हम बात करें तो चुनाव खर्च का अनुमान तो बहुत कम लगाया जाता है, पर वास्तव में चुनावी खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। हर कोई दल अपने मतदाता को लुभाने के लिए येन केन प्रकारेण प्रयास करते रहते हैं, जो कई बार सही तो कई बार गलत या अनैतिक भी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक दल द्वारा एक मतदाता को लुभाने के लिए सौ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो दूसरा दल या नेता तुरंत डेढ़ सौ रूपए देकर उसे अपनी तरफ

करने का प्रयास करने लग जाता है और यह अंधी– दौड़ चुनाव होने तक चलती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप चुनावी खर्च बढ़ जाते है।

अब तक का सबसे कम खर्चीला चुनाव वर्ष 1957 का रहा, जिस पर सिर्फ 30 पैसे एक मतदाता पर खर्च हुए थे देश के पहले चुनाव (वर्ष 1951–52) में जहाँ एक मतदाता पर 60 पैसे खर्च हुए थे वहीं 2019 में लगभग 72 रुपए और 2024 में यह राशि बढ़कर लगभग 243:-हो गई जो अब तक का सबसे महंगा चुनाव खर्च है।

चूँकि पहले जनसँख्या के साथ ही साथ जनसँख्या घनत्व भी कम था, तो चुनाव प्रचार हेतु टमटम, बैलगाड़ी, साइकिल रिक्शा का उपयोग कर लिया जाता था, पर अब वायुयान, रेल या सड़क परिवहन पर ही बहुत खर्च हो जाता है।

जैसे–जैसे मतदाता का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ता है, मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, परिसीमन आयोग द्वारा जनसंख्या का अवलोकन किया जाकर प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या बढाई जाती है, तो चुनावी खर्चे में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक ही होता है।

चुनाव में आम जनता ज्यादा से ज्यादा वोट दे, इस हेतु समय –समय पर सरकार द्वारा जागरूकता अभियान, प्रचार–प्रसार अभियान भी चलाये जाते है। संघीय मंत्रालय के प्रकाशन के अनुसार 15 वें, राष्ट्रीय चुनाव 1999 तक चुनाव में 60% से कम महिलाओं की उपस्थिति थी, किंतु 2014 में इसमें बढ़ोतरी हुई है और यह उपस्थिति 65.6 प्रतिशत हो गई है।

इसके अतिरिक्त नए मतदान केंद्र बनाया जाना तथा चुनावी वर्ष में पुराने चुनाव केन्द्रों का रखरखाव, रंगरोगन, कर्मचारियों के लिए आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था, सुरक्षा, संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाने में भी खर्चा होता है। विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन यह सब खर्चों के ही प्रकार है क्योंकि आज के डिजिटल युग में चुनाव केवल जमीन स्तर पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़े जाते है। सबसे अधिक चुनावी खर्च उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और बिहार में हुआ था।

इसके अलावा चुनाव में उपयोग होने वाली ईव्हीएम मशीन की खरीद एवं उसके रखरखाव के कारण जहाँ वर्ष 2019 में 20 से 25 करोड रुपए खर्च लगे थे, वहीं वर्ष 2023– 24 में यह खर्चा बढ़कर लगभग 1891-8 करोड रुपए तक पहुँच गया है।

सत्ता परिवर्तन के पश्चात भी खर्चों में बढ़ोतरी होती है क्योंकि वर्तमान में स्थापित सरकार अपना वर्चस्व और महत्ता सिद्ध करने के लिए पूर्व समय की सरकार जो भी योजना बनाती है, वह नवनिर्वाचित सरकार या तो पूरी तरह से बंद कर देती है या संशोधनों के साथ अपनी नई योजना को शुरू करती है।

भारत में बढ़ते चुनावी खर्च को रोकने के लिए देश में "एक देश–एक चुनाव" करवाए जाने की कवायत की जा रही है, जिससे देश की प्रशासनिक इकाइयों में लगे कर्मचारियों– अधिकारियों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही बची हुई धनराशि का उपयोग देश के विकास में किया जा सकेगाद्य इस हेतु सुझाव देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया गया है। विश्व की बात की जाये तो दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी में पहले से ही एक देश एक चुनाव पद्धति प्रचलन में है, जिसके अपने–अपने लाभ–हानि है।

देखा जाए तो एक देश एक चुनाव की अवधारणा नई नहीं है, बल्कि यह तो बहुत पुरानी है। वर्ष 1967 मे इस तरीके से देश में चुनाव संपन्न कराए गए थे, किन्तु कई राज्यों में कतिपय कारणों से विधान सभा भंग होने से मध्यावर्ती चुनाव किये गए, जिस वजह से यह संतुलन बिगड़ता गया और देश में अलग–अलग समय पर अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग चुनाव संपन्न किये जाने लगे। एक देश एक चुनाव कराये जाने के जहाँ फायदे है. वही इसके नुकसान भी है। देश में लगभग 30 लाख ईव्हीएम मशीन एवं वीवीपीएटी (वोटर वैरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) के रखरखाव पर भी खर्चा आएगा साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों का महत्व भी कम होगा, क्योंकि देश की समस्याओं के सामने स्थानीय समस्या को कोई अधिक महत्व नहीं मिलेगा, साथ ही इतने बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी।

चुनाव होने पर 5 वर्ष में एक बार स्थानीय नेता जनता से मिलते भी थे, भले ही मजबूरी में मिलते हो पर एक साथ चुनाव करवाए जाने पर अब नेता जनता से मिलेंगे ही नहीं। चुनाव आयोग द्वारा समय–समय पर चुनाव में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य की सूची प्रकाशित की जाती है, जिसको आधार मान कर सभी दलों को खर्च करना होता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए तो एक–एक वोट अमूल्य होता है, कई बार देखा भी जाता है कि एक पार्टी बहुत कम वोटो के अंतर से चुनाव हार जाती है, अतरूसभी दल ये अमूल्य मौका किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते और अपनी जी–जान लगा देते है ,भले ही कितना भी खर्च आ जाये क्योंकी सबको सत्ता का सुख भोगना है। अगर हम भारतीय चुनावी खर्चों का आकलन करें तो कई बार यह खर्च किसी देश के सकल घरेलु उत्पाद के बराबर हो जाते हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अगर हम चुनावी खर्च की मदों की बात करें, तो विशेष मदों में प्रचार–प्रसार, चुनाव में उपयोग होने वाली मशीनों की खरीदी, उनका रखरखाव, उम्मीदवार की यात्रा, रैलियों पर खर्च, नेताओं की सुरक्षा पर होने वाला खर्च, इन मदों पर सबसे ज्यादा खर्च होते हैं।

2018 में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों को बढते व्यय पर नियंत्रण रखने हेतु एक समिति भी बुलाई गई थी, पर किसी बड़ी पार्टी द्वारा यह बोलकर मना कर दिया गया कि जब खर्चों का विवरण देना ही है, तो खर्चों पर अंकुश क्यों लगाया जाए? 2019 में बीजेपी ने लगभग 1372 करोड़ खर्च किए थे, वहीं कांग्रेस ने लगभग 467 करोड़ खर्च किए थे। खर्चे पर अंकुश लगाए जाने से सभी दलों को समान अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि कोई दल ज्यादा पैसा खर्च करके मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा द्य मतदाता को भी अपने विवेक का उचित उपयोग करते हुए अपने मताधिकार का सही और देश के हित के लिए प्रयोग करना चाहिए ,जिससे देश का सही ढंग से विकास हो सके।

लॉ कमीशन की 205 वीं रिपोर्ट में चुनावी खर्च पर रोक का विरोध किया गया था क्योंकि 1969 में कॉर्पोरेट खर्च पर रोक लगा देने से, लोगों ने दूसरे तरीके अपनाए थे,जिससे भ्रष्टाचार व काला धन को बढ़ावा मिला था,अतरू सरकार को भी सोच विचार कर एक पुख्ता रणनीति तैयार करने के, अतिरिक्त मजबूत प्रशासनिक इकाई तैयार करनी चाहिए, जो भारत जैसे विशाल देश के लिए चुनावी खर्चो पर नियंत्रण रख सके।

*बंट रहे है पर्चे।*

*कम होंगे चुनावी खर्चे।।*

*हर तरफ है यही चर्चे।*

*अब मत करो कही सर्च।।*

*बस निभाओ वोट देने का फर्ज।*

टिप्पणी

परिकल्पना

परिकल्पना से तात्पर्य, सामान्य रूप से पूर्व अर्जित ज्ञान पर आधारित अनुमान से है।

अवधारणा/संकल्पना

अवधारणा से तात्पर्य किसी ऐसी चीज का मानसिक प्रतिनिधित्व है, जो वास्तव में उपस्थित हो, चाहे वह भौतिक वस्तु हो या कोई प्रक्रिया या ज्ञान। सरल शब्दों में किसी काम को करने की प्रक्रिया अवधारणा कहलाती है।

♦♦♦♦♦

6

# चुनावी प्राक्कलनः परिकल्पना बनाम संकल्पना

सजल जैन

विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज

चुनावी प्राक्कलन एक ऐसा विज्ञान और कला है जो लोकतंत्र के भविष्य को आकार देता है। यह मात्र आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि समाज, राजनीति, और अर्थव्यवस्था के गहन विश्लेषण का परिणाम है। परिकल्पना और संकल्पना, इन दो अवधारणाओं के बीच चुनावी प्राक्कलन का संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। 2024 के झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम इन दोनों दृष्टिकोणों के महत्व को उजागर करते हैं।

## परिकल्पना और संकल्पना का परिचय

परिकल्पना वह दृष्टिकोण है जो पिछले आंकड़ों, प्रवृत्तियों और मतदान पैटर्न पर आधारित होती है। इसमें पूर्वानुमानों के लिए सांख्यिकीय मॉडल, चुनावी सर्वेक्षण, और ऐतिहासिक परिणामों का उपयोग किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी पार्टी ने पिछली बार किसी क्षेत्र में 50% वोट प्राप्त किए हैं, तो परिकल्पना यही होगी कि वह इस बार भी इसी वोट प्रतिशत के आसपास प्रदर्शन करेगी।

दूसरी ओर, संकल्पना भविष्य के चुनावी परिदृश्य को लेकर नेताओं, पार्टियों, और मुद्दों की भूमिका पर केंद्रित होती है। इसमें भावनात्मक, सामाजिक, और स्थानीय मुद्दों को समझने का प्रयास किया जाता है। यह दृष्टिकोण समाज के बदलते स्वरूप, नए मुद्दों, और मतदाताओं को प्राथमिकताओं पर आधारित होता है।

हाल ही में हुए महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने संकल्पना व परिकल्पना के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया स इसे यह साबित हुआ कि यदि दोनों में समन्वय नहीं हो अथवा जमीनी मुद्दों को ध्यान में नहीं लिया जाए तो गणना गलत साबित हो सकती है।

## चुनावी प्राक्कलन में परिकल्पना और संकल्पना की भूमिका

1. मतदाता व्यवहार का विश्लेषण

परिकल्पना

क्या झारखंड में आदिवासी मतदाता स्थानीय दलों के पक्ष में वोट देंगे?

संकल्पनाः

आदिवासी पहचान और राजनीतिक भागीदारी।

2. चुनावी मुद्दों का निर्धारण

संकल्पनाएं जैसे विकास की राजनीति और धर्म आधारित ध्रुवीकरण पर आधारित परिकल्पनाओं का निर्माण।

उदाहरणः

परिकल्पना

क्या महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण माफी चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगी?

संकल्पनाः

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संकट का राजनीतिक प्रभाव।

3. प्रचार और संचार रणनीतियों का प्रभाव

चुनावी रणनीतियां परिकल्पनाओं पर आधारित होती हैं, लेकिन उनका ढांचा संकल्पनाओं से निर्धारित होता है।

परिकल्पनाः

क्या सोशल मीडिया प्रचार ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच सकता है?

संकल्पनाः

डिजिटल मीडिया का प्रभाव और पहुंच।

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024:परिकल्पना की प्रासंगिकता

झारखंड के चुनाव में परिकल्पना का महत्व स्पष्ट रूप से देखा गया। झारखंड में परंपरागत रूप से जनजातीय वोटों का वर्चस्व रहा है। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने जनजातीय क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए रखा था। परिकल्पना के अनुसार, 2024 में भी झामुमा को इन्हीं क्षेत्रों में बढ़त हासिल होनी चाहिए ।

हालांकि, झारखंड में भाजपा ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संकल्पना का सहारा लिया। भाजपा ने विकास और रोजगार के मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दे भाजपा की रणनीति के केंद्र में रहे। इसने झामुमो के परंपरागत वोट बैंक में ना तो सेंध लगाई और ना ही जीत में सफल रही स झारखंड की ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा स

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: संकल्पना की विजय

महाराष्ट्र के चुनावों ने दिखाया कि केवल परिकल्पना के सहारे चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। शिवसेना (शिंदे गुट) भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के गठबंधन ने पिछले चुनावों के आंकड़ों और परिकल्पना के आधार पर अपना चुनावी अभियान शुरू किया। उनकी रणनीति यह थी कि गठबंधन के कारण उन्हें एक स्थिर वोट बैंक मिला।

विपक्षी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट), और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल थी, ने विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा, मराठा आरक्षण, किसान आंदोलनों, और बुनियादी सेवाओं की कमी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को प्रभावित किया। इन मुद्दों पर संकल्पना आधारित अभियान ने परंपरागत वोटिंग पैटर्न को बदलना चाहा लेकिन परिणाम विपरीत रहे स भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 235 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले महाविकास आघाड़ी को 50 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा स

परिकल्पना की सीमाएँ

झारखंड और महाराष्ट्र के परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि परिकल्पना अपनी सीमाओं में बंधी होती है।

1. स्थिरता का भ्रम

परिकल्पना अक्सर मानती है कि समाज स्थिर है और पिछले चुनाव के मुद्दे वर्तमान में भी प्रासंगिक रहेंगे। झारखंड में जनजातीय क्षेत्रों में झामुमो की हार ने इस भ्रम को तोड़ा।

2. भावनात्मक पहलुओं की अनदेखी

परिकल्पना भावनात्मक और सामाजिक कारकों को आंकड़ों में तब्दील करने में असमर्थ रहती है। महाराष्ट्र में किसान आंदोलनों और मराठा आरक्षण जैसे भावनात्मक मुद्दों ने परिकल्पना आधारित पूर्वानुमानों को विफल कर दिया।

3. क्षेत्रीय मुद्दों का प्रभाव

परिकल्पना बड़े स्तर पर ट्रेंड देखती है, लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को अक्सर अनदेखा कर देती है।

संकल्पना की सफलता के कारण

संकल्पना आधारित दृष्टिकोण ने 2024 के चुनावों में सफलता पाई। इसके कुछ प्रमुख कारण हैंः

1. जमीनी स्तर की समझ

संकल्पना में स्थानीय मुद्दों, जनभावनाओं, और सामाजिक संरचनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ने इसे बखूबी अपनाया।

2. प्रेरणा और भावनाओं का उपयोग

मतदाता केवल आंकड़ों से प्रभावित नहीं होते, वे भावनाओं से जुड़ते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में संकल्पना ने भावनात्मक अपील को केंद्र में रखा।

3. वर्तमान परिस्थितियों का आकलन

संकल्पना पिछले आंकड़ों पर नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित होती है।

भविष्य की दिशाः परिकल्पना और संकल्पना का संतुलन

झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों ने यह सिखाया कि परिकल्पना और संकल्पना दोनों की अपनी भूमिका है। भविष्य के चुनावी प्राक्कलनों में इन दोनों दृष्टिकोणों का संतुलन आवश्यक है।

1. आंकड़ों और वास्तविकता का समन्वय

परिकल्पना और संकल्पना को एक साथ मिलाकर चुनावी अभियान चलाने से मतदाताओं तक प्रभावी संदेश पहुंचाया जा सकता है।

2. टेक्नोलॉजी का उपयोग

डाटा एनालिटिक्स और एआई की मदद से परिकल्पना को और सटीक बनाया जा सकता है।

3. समाज की बदलती प्रवृत्तियों पर ध्यान

संकल्पना को मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष और सिफारिशें

चुनावी प्राक्कलन केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह समाज और राजनीति के गहरे विश्लेषण का परिणाम है। झारखंड और महाराष्ट्र के 2024 के चुनावों ने यह सिद्ध किया कि परिकल्पना और संकल्पना दोनों की अपनी सीमाएँ और संभावनाएँ हैं। चुनावी सफलता के लिए इन दोनों दृ ष्टिकोणों का संतुलन ही सबसे प्रभावी रणनीति है।

1. परिकल्पना और संकल्पना का समन्वयः

चुनावी प्राक्कलन में परिकल्पना (आर्थिक मुद्दे, जातीय समीकरण) और संकल्पना (विकास, पहचान की राजनीति) दोनों का प्रभावी उपयोग आवश्यक है।

2. महाराष्ट्र और झारखंड से सीखः

महाराष्ट्र में आर्थिक मुद्दों और गठबंधन राजनीति ने चुनाव परिणाम प्रभावित किए।

झारखंड में क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय राजनीति की संकल्पना निर्णायक साबित हुई।

3. भविष्य के प्राक्कलन

अधिक सटीक चुनावी अनुमान के लिए डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी मॉडल का उपयोग बढ़ाना चाहिए।

4.राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संकल्पनाओं का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

चुनावी प्राक्कलन न केवल चुनावी परिणामों का पूर्वानुमान लगाता है, बल्कि समाज के भीतर मौजूद गहरी संरचनाओं को भी उजागर करता है। परिकल्पना और संकल्पना का प्रभावी समन्वय इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाता है।

सन्दर्भ


- भारत निर्वाचन आयोग। (2024)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिपोर्ट 2024। भारत निर्वाचन आयोग। https://eci-gov-in
- कुमार, पी., – शर्मा, आर। (2023)। महाराष्ट्र में राजनीतिक गठबंधन और मतदाता व्यवहार। भारतीय राजनीतिक विज्ञान पत्रिका, 78(4), 233–250A https://doi-org/10
- गुप्ता, आर। (2024, 2 दिसंबर)। महाराष्ट्र 2024 चुनाव परिणामः प्रमुख निष्कर्ष। इंडियन एक्सप्रेस। https://indianeÛpress-com
- पाटिल, एस। (2024)। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में जाति की भूमिका। मुंबई पॉलिटिकल स्टडीज प्रेस
- यादव, आर.,–सिंह, एम। (2023)। भारत में गठबंधन राजनीति का प्रभाव। एशियाई राजनीतिक विश्लेषण पत्रिका, 12(3), 145–160। https://doi-org/10.
- भारत निर्वाचन आयोग। (2023)। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता मतदान प्रवृत्तियाँ। भारत निर्वाचन आयोग। https://eci-gov-in
- देशमुख, ए। (2023, 15 नवंबर)। महाराष्ट्र चुनावों को आर्थिक मुद्दों ने कैसे आकार दिया। द हिंदू। https://www-thehindu-com
- चंद्रा, के। (2022)। आदिवासी पहचान चुनावी प्राक्कलनः परिकल्पना बनाम संकल्पना


♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

# सी जी एस

# वैश्विक अध्ययन केंद्र

## (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)


अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281